हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 177 लखनऊ, रविवार 22 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति संग की बैठक

रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने शनिवार को यहां प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें भारत–ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग विस्तार पर चर्चा की गयी। हैदराबाद हाउस में हुई वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार–विमर्श किया। वार्ता के दौरान भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा, विदेश सचिव विक्रम मिश्री

तथा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल उपस्थित थे। इससे पहले दा सिल्वा का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तथा पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति दा सिल्वा ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से भी मुलाकात की तथा राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।ब्राजील के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में ब्राजीलिया की व्यापार एवं निवेश संवर्धन एजेंसी (एपेक्सब्राजील) के पहले कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच श्एक्सश पर एक पोस्ट में कहा कि यह कार्यालय ब्राजील के उत्पादों और सेवाओं को विदेशों में बढ़ावा देने तथा ब्राजील की अर्थव्यवस्था के रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित करने में सहायक होगा। भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ दा नोब्रिगा ने दोनों नेताओं के बीच बढ़ते तालमेल को रेखांकित करते हुए कहा कि यह द्विपक्षीय संबंधों को ऐतिहासिक रूप से एक नये स्तर पर ले जा रहा है। उन्होंने बताया कि दा सिल्वा अपने साथ अब तक का सबसे बड़ा ब्राजीलिया का प्रतिनिधिमंडल लेकर आये हैं, जिसमें 11 से अधिक कैबिनेट मंत्री, 300 से ज्यादा कारोबारी और 50 मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं। दा सिल्वा की यह यात्रा मोदी की जुलाई 2025 में ब्रासीलिया यात्रा के बाद हो रही है, जो पांच दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील की पहली यात्रा थी। दोनों नेताओं ने जनवरी में टेलीफोन पर बातचीत के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान–प्रदान किया था और साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार के महत्व पर बल दिया था।

श्रीनगर के पास बड़ा हादसा, सीआरपीएफ वाहन नहर में गिरने से 7 जवान घायल

बीएनई

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पास शनिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वाहन के नहर में गिर जाने से कम से कम सात जवान घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार यह हादसा सुबह डागपोरा–उमरहेयर रोड पर अहमदनगर क्षेत्र में हुआ। बताया गया है कि चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण गाड़ी सड़क से फिसलकर नहर में जा गिरी। घटना के तुरंत बाद राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया और सभी घायल जवानों को तुरंत श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर है। घटना के बाद नहर से सीआरपीएफ वाहन को बाहर निकालने के लिए भी अभियान चलाया गया।

संक्षिप्त समाचार

आरएसएस से जुड़ा मानहानि मामला, राहुल भिवंडी की अदालत में पेश हुए, सपकाल को नया जमानतदार बनाया

एजेंसी

ठाणे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में नया जमानतदार पेश करने के लिए शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को अपना नया जमानतदार नामित किया। भिवंडी जाते समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने राहुल को काले झंडे दिखाए। वह सपकाल और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अदालत परिसर में पहुंचे।

अजित पवार की मौत के केस में आया नया मोड़

रोहित पवार ने रखी बड़ी डिमांड, किए बड़े खुलासे

एजेंसी

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश हादसे में 28 जनवरी को निधन हुआ था। इस घटना को घटित हुए तीन हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है। रोहित पवार ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे हादसे को गहरी साजिश करार दिया है। इसी के साथ उन्होंने हादसे से जुड़ी तकनीकी खामियों और विमान संचालक कंपनी पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के इस्तीफे की मांग की है। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि दुर्घटनाग्रस्त स्मंतरमज 45 विमान का संचालन करने वाली कंपनी वीएसआर वेंचर्स को सत्ताधारी दलों का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने दावा किया कि इस कंपनी के तार केंद्र और राज्य के प्रभावशाली नेताओं से जुड़े हैं। रोहित पवार ने सीधे तौर पर कहा कि डीजीसीए के कुछ अधिकारी तथ्यों को दबाने और कंपनी को क्लीन चिट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विमान में यात्रियों के सामान वाली जगह पर पेट्रोल के अतिरिक्त कैन रखे गए थे, जिसके कारण आग बेकाबू हुई। रोहित पवार के मुताबिक, क्रैश के समय विमान में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे ब्लैक बॉक्स की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े उन्होंने आरोप लगाया कि विमान की यांत्रिक स्थिति और रख–रखाव में भारी अनदेखी की गई थी। रोहित पवार ने प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा, ष्अजित पवार को न्याय केवल पीएम और गृहमंत्री ही दिला सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे प्रधानमंत्री को इस संबंध में ईमेल के जरिए पत्र लिखेंगे। इसके अलावा, उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी इस मुद्दे को संसद और सार्वजनिक मंचों पर उठाने का आग्रह किया। गौरतलब है कि 28 जनवरी, 2026 को बारामती एयरस्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान अजित पवार का चार्टर विमान क्रैश हो गया था। इस भीषण हादसे में अजित पवार समेत चालक दल के सदस्य और सुरक्षा अधिकारी–कुल 5 लोगों की जान चली गई थी।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को झटका, यौन शोषण के मामले में दर्ज होगी एफआईआर, कोर्ट का आदेश

बीएनई

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एडीजे रेप एवं पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एडीजे (पोक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर विधिवत विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह अर्जी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत दाखिल की गई थी। आरोप है कि संबंधित आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। आवेदक ने अदालत में कथित साक्ष्य के रूप में सीडी भी प्रस्तुत करने का दावा किया है। 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने पुलिस

रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था और सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब आदेश जारी होने के बाद मामले में विधिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि उन्हें न्यायालय से न्याय मिला है और वे प्रयागराज से वाराणसी स्थित विद्या मठ तक पैदल यात्रा निकाल कर लोगों के सामने तथ्य रखने की बात कह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया जा रहा है और आरोपों की सत्यता की जांच पुलिस विवेचना के बाद ही स्पष्ट होगी।

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले के बाद कहा : भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं, रिश्ते मजबूत बने रहेंगे

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके व्यापक टैरिफ फैसलों को अवैध घोषित करने के कुछ घंटों बाद स्पष्ट किया कि भारत के साथ ट्रेड समझौते में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत–अमेरिका व्यापारिक साझेदारी जारी रहेगी और दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए बढ़े हुए टैरिफ को रद्द कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग

का हवाला दिया गया। इस फैसले के बावजूद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का जिक्र करते हुए कहा, भारत के साथ हमारे रिश्ते शानदार हैं। हम भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत पहले रूस से तेल खरीद रहा था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि हम उस भयानक युद्ध (रूस–यूक्रेन) को खत्म करना चाहते हैं, जिसमें हर महीने हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मोदी एक महान व्यक्ति हैं, बहुत स्मार्ट लीडर। हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। उन्होंने पुरानी यादें ताजा करते हुए दावा किया कि उन्होंने टैरिफ के दबाव से भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रोका था, जिसमें 10 विमान गिराए गए थे और परमाणु खतरा मंडरा रहा था। ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी उनकी इस भूमिका की सराहना की और लाखों जानें बचने की बात कही। जब पत्रकारों ने भारत के साथ ट्रेड डील के भविष्य पर सवाल किया, तो ट्रंप ने कहा, कुछ नहीं बदलेगा। वे टैरिफ देंगे, हम नहीं देंगे। भारत के साथ डील यही है कि वे टैरिफ चुकाएं। पहले स्थिति उलटी थी, भारत हमें लूट रहा था, लेकिन अब यह एक निष्पक्ष समझौता है। हम उन्हें टैरिफ नहीं दे रहे, वे हमें दे रहे हैं। डील शुरू हो चुकी है और हम इसे नए तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ट्रंप ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में उन्होंने भारत पर रूस से तेल खरीद के लिए लगाए गए 25% टैरिफ हटा दिए थे और समझौते के तहत टैरिफ दर को 18% तक कम किया गया था। भारत ने अमेरिकी सामानों की खरीद बढ़ाने का वादा किया है।

अगले पांच वर्षों में घुसपैठियों को न केवल मतदाता सूची से बल्कि देश से भी निकाल दिया जाएगा : अमित शाह

एजेंसी

गुवाहाटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जोर दिया कि अगर भारत नक्सलियों से मुक्त हो सकता है, तो वह घुसपैठियों से भी मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में अवैध प्रवासियों को न केवल मतदाता सूची से बल्कि देश से भी निकाल दिया जाएगा। शाह असम पुलिस की 10वीं बटालियन के नए परिसर की आधारशिला

रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बटालियन के बारे में उन्होंने कहा कि इसका निर्माण घुसपैठियों के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर किया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता ने एक बार कहा था कि घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अवैध प्रवासी उसका वोट बैंक हैं। उन्होंने कहा, अतिक्रमण की गई जमीनों से घुसपैठियों को निकालना ही काफी नहीं है, उन्हें भारत से बाहर भी भेजना होगा। शाह ने कहा कि अगले पांच वर्षों में असम पूर्व और पूर्वोत्तर भारत का औद्योगिक केंद्र बन जाएगा। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए चुनाव मार्च–अप्रैल में होने की संभावना है।

जॉर्जिया में भारत के नए राजदूत अमित कुमार मिश्रा ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, मिला लेटर ऑफ क्रेडेंस

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत के जॉर्जिया में नियुक्त राजदूत अमित कुमार मिश्रा ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

से मुलाकात की और अपना लेटर ऑफ क्रेडेंस प्राप्त किया। राष्ट्रपति ने उन्हें उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं और विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में भारतदृजॉर्जिया संबंध और अधिक सुदृढ़ तथा बहुआयामी बनेंगे।

2004 बैच के अनुभवी राजनयिक

बिहार के दरभंगा जिले के मूल निवासी अमित कुमार मिश्रा भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 2004 बैच के एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनयिक हैं। दो दशकों से अधिक की सेवा अवधि में उन्होंने विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनकी विशेषज्ञता अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बहुपक्षीय कूटनीति, वाणिज्य दूतावास सेवाओं, आर्थिक सहयोग और नीतिगत निर्माण जैसे क्षेत्रों में है। भारत और जॉर्जिया के बीच पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। द्विपक्षीय सहयोग व्यापार और निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि उद्योग, कृषि, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा तथा जन–से–जन संपर्क जैसे क्षेत्रों में निरंतर विस्तार कर रहा है।

भारत और जॉर्जिया के बीच सहयोग बढ़ने की अपार संभावनाएं मौजूद

मिश्रा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और जॉर्जिया के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को और अधिक बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उनके अनुभव और नेतृत्व से द्विपक्षीय संबंधों में नई गति आने तथा रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को और सुदृढ़ करने की अपेक्षा है। अमित कुमार मिश्रा शीघ्र ही त्बिलिसी में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

सीबीआई ने 10 लाख की घूस लेते पांच को रंगे हाथ धरा, लखनऊ समेत एक दर्जन ठिकानों पर छापा मारा

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उड़ीसा में इमली प्रसंस्करण इकाई का ठेका दिलाने के एवज में दस लाख की रिश्वत लेते वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (वापकोस) का प्रोजेक्ट मैनेजर और ठेकेदार समेत पांच आरोपी शनिवार को गिरफ्तार किए गए। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो लखनऊ की टीम ने ये कार्रवाई की। आरोपियों लखनऊ, देवरिया, गाजीपुर और भुवनेश्वर स्थित नौ

ठिकानों पर छापे भी मारे। रिश्वतखोरी के खेल में शामिल पांच और आरोपियों की तलाश जारी है। सीबीआई के मुताबिक मूलरूप से देवरिया निवासी (वर्तमान में लखनऊ में निवास) पंकज दुबे वापकोस में प्रोजेक्ट मैनेजर है। उड़ीसा में इमली प्रसंस्करण इकाई का 11.81 करोड़ रुपये का ठेका 13 जनवरी 2026 को इकाना इंटरप्राइज के प्रोपराइटर बबलू सिंह यादव को दिलाया। इसमें एवज में कई किश्तों में करोड़ों की रिश्वत वसूली जानी थी। शनिवार को पंकज की तरफ से बिचौलिए राहुल वर्मा व बबलू की ओर बिचौलिए राजेश कुमार के जरिये दस लाख रुपये की रिश्वत की किश्त का लेनदेन किया गया। इसमें पंकज का ड्राइवर शुभम पाल भी शामिल रहा। इनपुट के आधार पर सीबीआई की टीम ने छापा मारकर इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दस लाख रुपये भी बरामद किए। सीबीआई ने आरोपियों के ठिकानों पर छापा मारा। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी व आशियाना में चार जगह छापे पड़े। इसके अलावा देवरिया में एक, गाजीपुर में दो और भुवनेश्वर में दो ठिकानों पर छापा मारकर सीबीआई सुबूत जुटाए।

2029–30 तक छह करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया दावा

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के लक्ष्य को और बड़ा करते हुए 2029–30 तक छह करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को यह जानकारी दी और कहा कि इस दिशा में सरकार चरणबद्ध तरीके से काम करेगी।

10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई

उन्होंने बताया कि लखपति दीदी उन महिलाओं को कहा जाता है जिनकी वार्षिक शुद्ध आय एक लाख रुपये या उससे अधिक होती है। वर्तमान में देशभर में 3.01 करोड़ महिलाएं इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं और करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी हुई हैं। मंत्री ने कहा कि अब प्रधानमंत्री ने लक्ष्य बढ़ाकर छह करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्देश दिया है और इसके लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने माना कि पहले तीन करोड़ का लक्ष्य हासिल करना अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि कई महिलाओं की आय पहले से 50 से 60 हजार रुपये के बीच थी, लेकिन अब कम आय वाली महिलाओं की आमदनी बढ़ाना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही एक विशेष अभियान चलाएगी, जिसके तहत उन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा जो अभी तक इससे बाहर हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

संपादकीय

कर्नाटक में देसी बीज बचाने वाली महिलाएं

कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले की सिरसी तालुका में महिला किसानों का समूह है, जो जंगल में घरेलू कृषि बागवानी को बढ़ावा देता है। परंपरागत देसी बीजों, जैव विविधता और पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण करता है। वनश्री नामक संस्था के काम से ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों के लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। आज इस अनूठे महिला समूह के बारे में बात करना चाहूंगा, जिससे देसी बीजों को बचाने की इस पहल को जाना जा सके। जलवायु बदलाव के दौर में इसके महत्व को समझा जा सके। मैं कर्नाटक में वनश्री के काम को देखने के लिए कुछ साल पहले गया था। कई गांव घूमा था। और महिला समूह के सदस्यों से मिला था। इसके बाद भी वनश्री के कार्यकर्ताओं से एक दो बार अलग–अलग कार्यक्रमों में मुलाकात हुई है। यहां महिलाओं ने लगातार देसी बीज बचाने, विशेषकर सब्जियों के बीज संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे देसी बीजों के साथ पारंपरिक ज्ञान भी बचाया जा सके। जलवायु बदलाव के दौर में प्रतिकूल परिस्थितियों, जैव विविधता व पर्यावरण को बचाया जा सके। इससे न केवल गांव, कस्बों, शहरों की महिलाओं को जोड़ा है, बल्कि दूरदराज के आदिवासियों महिलाओं को भी जोड़ा है और उन्हें प्रशिक्षित किया है। वनश्री की शुरूआत 2001 में हुई। सुनीता राव ने इसकी पहल की थी, जो अपनी पढ़ाई के दौरान ही जापान के मशहूर कृषि वैज्ञानिक मोसानोबू फुकूओका से मिली थीं और प्रभावित हुई थीं। तब वह पांडिचेरी में पढ़ रही थीं, उस दौरान फुकूओका वहां आए थे। उनसे प्रभावित होकर वैसा ही काम करना चाहती थीं। एक जमाने में फुकूओका की किताब एक तिनके से आई क्रांति काफी चर्चित रही थी। फुकूओका ने खुद जापान में उनके खेत में प्राकृ तिक खेती के प्रयोग किए थे, जो बाद में दुनिया भर में चर्चित हुए। संस्था की कार्यकर्ता सुनीता राव ने बताया था कि वनश्री को काम करते हुए कई साल हो गए हैं। इससे जुड़कर बड़ी संख्या में महिला किसान जंगल घरेलू कृषि बागवानी का अनूठा काम कर रही हैं। इससे खाद्य, चारा, ईंधन, रेशा, औषधियां मिलती हैं। यह बेहतर स्वास्थ्य के साथ टिकाऊ जीवनशैली का आधार है। प्रकृति से जुड़ने का एक माध्यम भी है। सुनीता राव बताती हैं कि इसकी शुरूआत अनौपचारिक रूप से हुई। जब भी हम किसी के घर जाते थे तब वे सबसे पहले उनका सब्जी का बगीचा दिखाते थे, बाद में घर के अंदर ले जाते थे। उनके लिए सब्जी का बगीचा बहुत महत्वपूर्ण होता था। यह बगीचा घर के बाहर छोटे हिस्से में होता है। एक एकड़ से कम या ज्यादा भूमि के टुकड़े में हो सकता है। जिसमें मिश्रित फसलें होती हैं। विविध तरह की सब्जियां, फल– फूल, जंगली कंद–मूल व औषधिपूर्ण पौधे होते हैं। वे आगे बताती हैं कि श्ये महिलाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर व स्वावलंबी हैं। वे अपने बगीचे में सब्जियां व फल उगाती हैं। फसल कटाई के बाद बीजों को चुनती हैं, उन्हें संभालती हैं, और उनका आदान–प्रदान करती हैं। परंपरागत बीजों की धरोहर व उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान को सहेजती हैं। मैं भी ऐसा ही कुछ काम करना चाहती थी। देसी बीजों का संरक्षण करना चाहती थी, परंपरागत ज्ञान एकत्र करना चाहती थी। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को जोड़ने की इच्छा थी। वनश्री की शुरूआत इसी तरह से हुई। वनश्री ने इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अलग–अलग समय में कई तरह के काम किए हैं। उन्होंने जगह–जगह जाकर देसी बीज एकत्रित किए, आपस में आदान प्रदान किए, उनके गुणधर्म जाने, और इसका प्रचार– प्रसार किया। इस संस्था ने कोविड के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व स्वस्थ रहने के लिए पारंपरिक काढ़े को बढ़ावा दिया है। यह हल्दी, अदरक, काली मिर्च, ब्राम्ही, तुलसी, अजवाइन, जीरे का उपयोग कर बनाया जाता है। इस काढ़े को दूध या पानी के साथ पीते हैं। लेमनग्रास, अदरक व तुलसी की चाय पी। यह पारंपरिक नुस्खा सदियों से आजमाया गया है, जो लोगों के अनुभव व पारंपरिक ज्ञान से निकला है। वनश्री ने अखबारी कागज के गमले बनाए हैं। उनमें बीज और पौधे रोपकर स्थानीय स्तर पर वितरित किए। इस मुहिम में स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में कुछ युवा भी जुड़े। वनश्री के काम के प्रचार–प्रसार में डाकघर व डाकिया का योगदान अहम है। एक डाकिया ने शुरूआत में पर्चे बांटने में मदद की थी। पारंपरिक बीजों के प्रचार–प्रसार और संरक्षण के लिए हर साल मलनाड़ मेला होता है। इसके आयोजन में वनश्री भी शामिल है। इससे ग्रामीण व शहरी समुदायों को जोड़ने की कोशिश है। इसे मलनाड वार्षिक मेला कहते हैं, जो मेलनाडु पहाड़ी शृंखला के नाम पर है। जिसमें महिला किसान व वनस्त्री के सदस्य आते हैं। उनके खेती व जंगल के उत्पाद लाते हैं, जिसमें बीज, औषधीय पौधे, खाद्य व गैर खेती खादय व हस्तशिल्प होता है।

राशिफल

मेष :– भावुकता वश संबंधों में भावनात्मक शोषण की आशंका है। पूर्वाग्रह वश अपने निकटस्थ सम्बन्धों के बारे में गलत धारणा पालना ठीक नहीं। सम्बन्धों की मधुरता हेतु आपस में विास कायम करें।

बृषभ :– व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। परिश्रम से आर्थिक लाभ के योग हैं। अत्यधिक भावुकता से भावनात्मक शोषण की भी आशंका है। भौतिक जगत से प्रभावित मन भविष्य को लेकर चिन्तित होगा।

मिथुन :– किसी अचल सम्पत्ति क्रय हेतु प्रयत्न तीव्र। अपने भाग्य को कोसना छोड़ अपने समय का सकारात्मक दिशा में लगावें। मान–प्रतिष्ठा में बृद्धि तो होगी परन्तु इससे अभिमानी न बनें।

कर्क :– समाजिक मान–सम्मान व वर्चस्व में बृद्धि होगी। व्यावसायिक क्षेत्र के प्रतिभा में निखार आयेगा। आपके स्थितियों में आकस्मिक सुधार के आसार बन रहें। कल्पनाएं साकार होती नजर आएंगी।

सिंह :– नये कायरे में पूंजी निवेश हेतु धनाभाव अवरोधक होगा। आपमें दूसरों को आकर्षित करने की अभूतपूर्व क्षमता है इसका भरपूर लाभ मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में परिश्रमानुकूल सफलता प्राप्त होगी।

कन्या :– रोजगार के क्षेत्र में किये गये कर्म का फल सफलता का आगाज कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में परिश्रमानुकूल सफलता प्राप्त होगी। परिजनों की सुख–सुविधा के प्रति मन चिन्तित होगा।

तुला :– प्रणय सम्बन्ध में केन्द्रित मन प्रियतम से मिलने के लिऐ ब्याकुल होगा। किसी खास मुद्दे को लेकर परिजनों के मतभेद का सामना करना पड़ेगा। प्रयासरत क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी।

वृश्चिक :– अच्छे अवसरों का लाभ उठानें में सक्षम बनें। जीवन में नीरसता को कम करने के लिए मन को सकारात्मक दिशा देवें। व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता से मन उत्साहित होगा।

धनु :– भावुकतावश किसी सम्बन्धी की बातें मन को कष्ट पहुचा सकती हैं। अपने अन्दर नए उर्जा की अनुभूति करेंगे। लेकिन बिगड़े हुए सम्बन्धों को सुधारने की चेष्टा करें। कार्य क्षेत्र में नये आसारों से उत्साहित होंगे।

मकर :– उच्छृंखल व मजाकिया स्वभाव आस–पास के वातावरण में महत्ता तो बढ़ाएगा। रोजगार में अपनी स्थिति को लेकर मन में हीनता का वाश होगा। महत्वपूर्ण पारिवारिक दायित्वों के पूर्ति के आसार बनेंगे।

कुंभ :– परिवार में किसी की अस्वस्थता से मन चिन्तित होगा। परिवारिक जिम्मेदारियां मन को बोझिल करेंगी। कोई अवरोधित काम के प्रति मन विशेष रूप से चिन्तित होगा। शिक्षा–प्रतियोगिता में प्रयत्न सार्थक होगा।

मीनः– सरल व मिलनसार स्वभाव से संबंधों में लोकप्रिय होंगे। भौतिक सुख–साधनों की लालसा में व्यय के योग हैं। जीविका क्षेत्र में परिश्रम सार्थक होगा। भावना प्रधान मन जल्द ही दूसरों से प्रभावित हो जाता है।

रफ्तार की कीमत : सड़क पर बुझता युवाओं का भविष्य

– डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत में सड़क हादसों में युवाओं की लगातार हो रही मौतें आज एक ऐसी सच्चाई बन चुकी हैं, जिसे नज़रअंदाज़ करना अब संभव नहीं है। हर दिन अख़बारों के पन्ने और न्यूज़ चौनलों की सुर्खियाँ हमें यह याद दिलाती हैं कि सड़कें कितनी असुरक्षित होती जा रही हैं। इन हादसों में सबसे अधिक प्रभावित युवा वर्ग हो रहा हैकृ वह वर्ग, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है। यह स्थिति न केवल दुखद है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गहरी चेतावनी भी है। सड़क दुर्घटनाएँ अचानक होने वाली घटनाएँ नहीं होतीं, बल्कि ये अक्सर मानवीय लापरवाही और गैर–जिम्मेदाराना व्यवहार का परिणाम होती हैं। तेज़ रफ्तार से वाहन चलाना, यातायात नियमों की अनदेखी करना, गलत दिशा में वाहन ले जाना, नींद या थकान की अवस्था में ड्राइव करना, शराब या नशे का सेवन करके गाड़ी चलाना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमालकृये सभी कारण मिलकर सड़क को मौत का रास्ता बना देते हैं। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से अधिकांश हादसे पूरी तरह रोके जा सकते हैं, यदि थोड़ी–सी सावधानी और समझदारी दिखाई जाए। युवा अवस्था जोश, आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति से भरी होती है। यही गुण जब अनुशासन और जिम्मेदारी से जुड़े हों, तो प्रगति का मार्ग बनाते हैं, लेकिन जब यही जोश लापरवाही में बदल जाए, तो विनाश का कारण बनता है। आज कई युवा तेज़ रफ्तार को शान और नियम तोड़ने को साहस समझने लगे हैं। "कुछ नहीं होगा" या "मैं संभाल लूँगा" जैसी सोच उन्हें खतरनाक फैसले लेने के लिए प्रेरित करती है। दुर्भाग्यवश, एक छोटी–सी गलती पूरे जीवन को समाप्त कर देती है। आधुनिक जीवनशैली और तकनीक ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। मोबाइल फोन आज जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान इसका इस्तेमाल जानलेवा साबित हो रहा है। एक पल की असावधानी, एक मैसेज पढ़ने या कॉल उठाने की कोशिश कई जिंदगियों को छीन सकती है। इसके बावजूद लोग इस खतरे को गंभीरता से नहीं लेते। यही उदासीनता सड़क हादसों की बढ़ती संख्या का एक बड़ा कारण है। शराब पीकर वाहन चलाना भी भारत में सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। कई लोग इसे अपराध नहीं, बल्कि सामान्य बात समझते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी के बाद खुद गाड़ी चलाने का आत्मविश्वास, या यह सोच कि "थोड़ी–सी शराब से क्या फर्क पड़ेगा", अक्सर घातक सिद्ध होती है। नशे की हालत में प्रतिक्रिया समय कम हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा, नींद की झपकी और थकान भी एक गंभीर लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला कारण है। लंबी दूरी की यात्रा, रात में ड्राइविंग या लगातार काम के बाद वाहन चलाना शरीर और मस्तिष्क पर भारी पड़ता है। कई हादसे केवल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि चालक कुछ सेकंड के लिए झपकी ले लेता है। यह कुछ सेकंड किसी के पूरे जीवन पर भारी पड़ सकते हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर कई प्रयास किए गए हैं। यातायात नियम बनाए गए हैं, जुर्माने बढ़ाए गए हैं, हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य किया गया है और जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कानून तभी प्रभावी होते हैं, जब लोग उन्हें दिल से स्वीकार करें। केवल डर के कारण नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं है; इसके लिए सोच और व्यवहार में बदलाव जरूरी है। सड़क सुरक्षा को केवल प्रशासन की जिम्मेदारी मान लेना एक बड़ी भूल है। यह हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। एक चालक के रूप में हमारी लापरवाही न केवल हमारी जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के जीवन को भी जोखिम में डालती है। पैदल चलने वाले, साइकिल सवार, बुजुर्ग, बच्चेकृसभी हमारी एक गलती का शिकार बन सकते हैं। परिवार और शिक्षा व्यवस्था की भूमिका भी इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने से पहले उन्हें यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा का सही ज्ञान दें। केवल वाहन चलाना सिखा देना पर्याप्त नहीं है; सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग की आदत डालना ज़रूरी है। स्कूलों और कॉलेजों में भी सड़क सुरक्षा को लेकर नियमित

जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए, ताकि युवा उम्र से ही इन मूल्यों को अपनाएँ। मीडिया की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। फिल्मों और विज्ञापनों में अक्सर तेज़ रफ्तार और जोखिम भरी ड्राइविंग को रोमांच और बहादुरी के रूप में दिखाया जाता है। इसका प्रभाव युवाओं पर गहरा पड़ता है। ज़रूरत है कि मनोरंजन के माध्यमों में भी जिम्मेदार संदेश दिए जाएँ और सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। समाज के स्तर पर भी सोच में बदलाव की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि नियम तोड़ना चालाकी नहीं, बल्कि गैर–जिम्मेदारी है। शराब पीकर या बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले को शाबाशी नहीं, बल्कि रोक और समझाइश मिलनी चाहिए। जब तक लापरवाही पर सामाजिक अस्वीकार नहीं होगा, तब तक इस समस्या पर काबू पाना मुश्किल है। आज सड़क हादसों में होने वाली मौतें केवल आंकड़े नहीं हैं। हर मौत के पीछे एक परिवार का उजड़ना, माता–पिता के सपनों का टूटना और समाज की एक संभावनाशील शक्ति का समाप्त होना छिपा होता है। युवा देश की रीढ़ होते हैं। उनकी असमय मृत्यु न केवल परिवार, बल्कि राष्ट्र के लिए भी अपूरणीय क्षति है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और संस्थागतकृ तीनों स्तरों पर प्रयास करने होंगे। व्यक्तिगत स्तर पर हर चालक को यह संकल्प लेना होगा कि वह नियमों का पालन करेगा और दूसरों की सुरक्षा का सम्मान करेगा। सामाजिक स्तर पर हमें सुरक्षित ड्राइविंग को संस्कार के रूप में अपनाना होगा। और संस्थागत स्तर पर कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर जागरूकता की आवश्यकता होगी। अंततः, सड़क पर सुरक्षित रहना केवल अपनी जान बचाने का सवाल नहीं है, बल्कि यह मानवता और जिम्मेदारी का प्रश्न है। थोड़ी–सी सावधानी, धैर्य और अनुशासन न जाने कितनी जिंदगियों को बचा सकता है। अगर हम आज नहीं चेते, तो कल यह त्रासदी किसी भी घर का दरवाज़ा खटखटा सकती है। युवाओं की ज़िंदगी अनमोल हैकृइसे लापरवाही की भेंट चढ़ने से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

असमानताओं पर प्रहार, समानता का विस्तारः एक सार्थक पुकार

–ललित गर्ग

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के समय में केवल असमानताओं पर प्रहार एवं समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम "समावेश को सशक्त बनानाः सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना" हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं–चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय–प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है। आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम–आधारित रोजगार असुरक्षित होते जा रहे हैं। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। ग्रामीण और शहरी, विकसित और विकासशील, पुरुष और महिला, सक्षम और दिव्यांग–इन सबके बीच संसाधनों की असमान पहुंच सामाजिक तनाव को जन्म देती है। ऐसे समय

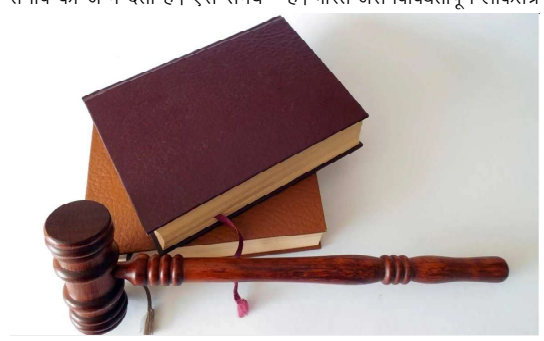

में सामाजिक न्याय का अर्थ है इन अंतरों को पहचानना और उन्हें पाटने के लिए लक्षित, संवेदनशील और पारदर्शी नीतियों का निर्माण करना। सम्मानजनक कार्य की अवधारणा भी सामाजिक न्याय के केंद्र में है। केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा कार्य–संस्कृति बनाना आवश्यक है जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य–परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह मानव गरिमा के साथ जुड़ा हो। यदि विकास केवल आंकड़ों में सीमित रह जाए और आम नागरिक के जीवन में राहत न ला सके, तो वह विकास नहीं, केवल विस्तार है। कोविड–19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संकट किसी भी समाज को अचानक अस्थिर कर सकता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक–इन सभी के लिए संरक्षित ढांचा ही न्यायपूर्ण समाज की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का विचार ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भी सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक असमानताओं से भी जुड़ा है। समकालीन भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशा–पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि सामाजिक न्याय विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि समावेशन की नीति के माध्यम से स्थापित हो। "संतुष्टिकरण" बनाम "तुष्टिकरण" की अवधारणा इसी दिशा में एक वैचारिक संकेत है, जो समाज को जोड़ने की बात करती है। फिर भी चुनौतियां शेष हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती जीवन–यापन लागत आम नागरिक के लिए वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंतोष और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। यदि नागरिक स्वयं को असुरक्षित, असमान या उपेक्षित अनुभव करें, तो सामाजिक न्याय का आदर्श खोखला प्रतीत होने लगता है। आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में देखा जाए। हमने आचरण की पवित्रता एवं पारदर्शिता की बजाय कदाचरण एवं अनैतिकता की कालिमा का लोकतंत्र बना रखा है। ऐसा लगता है कि धनतंत्र एवं सत्तातंत्र ने जनतंत्र को बंदी बना रखा है। हमारी न्याय–व्यवस्था कितनी भी निष्पक्ष, भव्य और प्रभावी हो, फ्रांसिस बेकन ने ठीक कहा था कि 'यह ऐसी न्याय–व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की यंत्रणा के लिये दस अपराधी दोषमुक्त और रिहा हो सकते हैं।' रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था कि 'मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है।' लेकिन हमारे देश के कानून एवं शासन व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता, आम आदमी सजा का जीवन जीने को विवश है। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक एकता भंग नहीं की जा सकती। शासन और प्रशासन की प्रत्येक नीति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। यदि शक्ति के स्रोत जनहित में प्रयुक्त न हों, तो वे असंतोष और अविश्वास को जन्म देते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। क्या हमारा लोकतंत्र समानता का लोकतंत्र है या विभेद का? क्या हमारी स्वतंत्रता सबके लिए समान अवसर लेकर आई है या केवल कुछ वर्गों तक सीमित है? क्या हमारी नीतियां पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित हैं या वे जटिलता और असमानता को बढ़ा रही हैं? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोजना ही इस दिवस की सार्थकता है। सामाजिक न्याय केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर उठकर यदि नागरिक परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, तो सामाजिक ताने–बाने को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा संस्थान, नागरिक संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच–सभी को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और डिजिटल नवाचार नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन अवसरों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। अन्यथा विकास की गाड़ी कुछ लोगों को आगे ले जाएगी और शेष को पीछे छोड़ देगी। समावेशन का सशक्तिकरण इसी असंतुलन को रोकने का प्रयास है। प्रतिदिन कोई न कोई कारण महंगाई को बढ़ाकर हम सबको और धक्का लगा जाता है और कोई न कोई टैक्स, अधिभार हमारी आय को और संकुचित कर जाता है। जानलेवा प्रदूषण ने लोगों की सांसों को बाधित कर दिया, लेकिन हम किसी सम्यक् समाधान की बजाय नये नियम एवं कानून थोप कर जीवन को अधिक जटिल बना रहे हैं। सामाजिक न्याय व्यवस्था तभी सार्थक है जब आम जनता निष्कंटक एवं समस्यामुक्त समानता का जीवन जी सके। 2026 का यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि न्याय और विकास एक–दूसरे के पूरक हैं। शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग सामाजिक न्याय से होकर ही गुजरता है। यदि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ जीवन जी सके, तभी हम कह सकेंगे कि हमने सामाजिक न्याय के आदर्श को साकार किया है। इस तरह सामाजिक न्याय केवल नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि चेतना का प्रश्न है। यह हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों में परिलक्षित होना चाहिए। जब नागरिक और शासन दोनों मिलकर समानता, गरिमा और अवसर की संस्कृति का निर्माण करेंगे, तभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। समावेश को सशक्त बनाकर और असमानताओं की खाई को पाटकर ही हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, अधिक मानवीय और अधिक स्थायी हो।

द्रमुक–कांग्रेस में अनबन का नियंत्रण कांग्रेस हाईकमान ने लिया

–नोरा चोपड़ा

तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कझगम–कांग्रेस गठबंधन के अंदर चल रही अनबन पर कांग्रेस हाईकमान ने पूरी तरह से सीधा कंट्रोल कर लिया है। हालांकि 22 फरवरी से फॉर्मल बातचीत शुरू होने वाली है लेकिन कांग्रेस नेताओं के सार्वजनिक बयानों से पहले ही इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि यह अनबन असली है या सोची–समझी मोलभाव की रणनीति। इसकी शुरुआती चिंगारी कांग्रेस की सीटों के बड़े हिस्से और गठबंधन के सत्ता में लौटने पर शासन में ज्यादा तय भूमिका की मांग लगती है। सांसद मणिकम टैगोर और रणनीतिकार प्रवीण चक्रवर्ती जैसे कांग्रेस नेताओं के मुखर बयानों से यह मुद्दा और बढ़ गया है, जिन्होंने एक्टर–पॉलिटिशियन विजय की पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम के साथ जुड़ने की संभावना सहित दूसरे पॉलिटिकल अलायंस के बारे में सार्वजनिक रूप से इशारा किया है। लेकिन हाल ही में, सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कनिमोझी के जरिए द्रमुक नेतृत्व को साफ–साफ बता दिया है कि उनकी पार्टी ऐसी किसी भी रणनीति पर जोर नहीं देगी जिससे गठबंधन में तनाव पैदा हो, जिसमें पावर–शेयरिंग पर बातचीत भी शामिल है। कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव से पहले कोई दूसरा गठबंधन चुनने या विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टी.वी.के.) के साथ जाने के किसी भी ऑप्शन से मना कर दिया है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि द्रमुक ने एक इनडायरैक्ट अल्टीमेटम दिया है कि कांग्रेस गठबंधन में रह सकती है लेकिन सरकार में हिस्सेदारी के बिना और अगर इससे पावर–शेयरिंग पर कोई जोर पड़ता है, तो वह छोड़ने के लिए आजाद हैं। ऐसे भी सुझाव हैं कि द्रमुक ने गठबंधन को आसानी से जारी रखने के लिए प्रवीण चक्रवर्ती और मणिकम टैगोर जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बयानबाजी के बावजूद, दोनों पार्टियां भाजपा विरोधी एकता को एक जोडने वाली ताकत के तौर पर जोर दे रही हैं। कर्नाटक में नहीं थम रही सत्ता के लिए खींचतान रू कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर सत्ता की खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही, ऐसे में उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि लीडरशिप में बदलाव का फैसला पहले ही हो चुका है और चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया सही समय पर इसकी घोषणा करेंगे। शिवकुमार ने सोशल वैल्फेयर मिनिस्टर डा. एच.सी. महादेवप्पा के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी, जिन्होंने कहा था कि कर्नाटक में पावर–शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में नेतृत्व मजबूत हैं और इसमें बदलाव की संभावना से इंकार किया। हालांकि, शिवकुमार ने कहा कि वह महादेवप्पा या दूसरे नेताओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। इस बीच, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के वफादार कहे जाने वाले 22 कांग्रेसी विधायक अपने खर्चे पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्राइवेट टूर पर जाने के लिए एक साथ आए हैं, जबकि विधायकों का दूसरा बैच भी उनके साथ जाने के लिए तैयार है। इस कदम को बड़े पैमाने पर सिद्धारमैया की यह संकेत देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि उनके पास कांग्रेस विधायकों के बहुमत का सपोर्ट है। शिवकुमार 'टॉप पोस्ट' के लिए फोकस में बने रहना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस हाईकमान ने केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में आने वाले असेंबली इलैक्शन खत्म होने तक वेट एंड वॉच अप्रोच का संकेत दिया है। प्रियंका गांधी का असम दौरा रू असम असेंबली इलैक्शन से पहले, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुवाहाटी में भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकार के खिलाफ 20 प्वॉइंट चार्जशीट जारी की है और प्रशासन पर करप्शन में लिप्त होने और अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने के लिए अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

SIR के अंतर्गत 22 फरवरी को प्रदेशभर के बूथों पर चलाया जा रहा विशेष अभियान

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के अन्तर्गत दावा एवं आपत्ति अवधि में अधिक से अधिक संख्या में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित कराने तथा मतदाता सूची को शुद्ध करने के उद्देश्य से दावा एवं आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु चार विशेष अभियान दिवस आयोजित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देशों के क्रम में पूर्व में दिनांक 11 जनवरी, 18 जनवरी तथा 31 जनवरी, 2026 को विशेष अभियान दिवस आयोजित किये गये थे। इसी कड़ी में रविवार, 22 फरवरी 2026 को प्रदेश के समस्त मतदेय स्थलों पर चौथा विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान दिवस को सफल बनाने के लिए समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष अभियान दिवस में प्रत्येक मतदेय स्थल पर प्रातः 10रू30 बजे से अपराह्न 1रू30 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उपस्थित रहेंगे। सभी बीएलओ के पास 6 जनवरी, 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची तथा पर्याप्त संख्या में सभी प्रकार के फार्म यथा 6, 6A, 7 एवं 8 उपलब्ध रहेंगे। विशेष अभियान में प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था होगी जहाँ मतदाताओं को फार्म भरने में सहायता प्रदान की जाएगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को अभियान तिथि की जानकारी देते हुए उनसे सहयोग प्राप्त किया जाएगा। सभासदों, ग्राम प्रधानों एवं स्वयंसेवकों का भी नियमानुसार सहयोग लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान दिवस के पर्यवेक्षण हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भ्रमणशील रहते हुए विशेष अभियान को सफल बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने समस्त नागरिकों से अपील की है कि विशेष अभियान दिवस–22 फरवरी, 2026 को अपने बूथ पर जाकर अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम 6 जनवरी, 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में अवश्य जाँच लें। यदि किसी पात्र सदस्य का नाम मतदाता सूची में अकिंत नही है अथवा ऐसे सदस्य जिनकी आयु 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, उनका भी फार्म 6 घोषणा पत्र सहित भरवाकर अपने बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध करा दें अथवा ECINET मोबाइल एप्लीकेशन या voters.eci.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आलेख्य मतदाता सूची में अंकित अपनी प्रविष्टि में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए फॉर्म 8 भरा जा सकता है।

योगी सरकार बड़ा तोहफा, 2.51 लाख किसानों को दिया 285 करोड़ रुपये का फसल मुआवजा

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 2.51 लाख से अधिक किसानों को

फसल मुआवजे के रूप में 285 करोड़ रुपये प्रदान किए और कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न अनिश्चितताओं से बचाया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान अपनी फसलों का बीमा कराते हैं, वे आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता के हकदार हैं। योगी ने कहा, राज्य के 2.51 लाख किसान परिवारों को फसल क्षति मुआवजे के रूप में 285 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। फसल बीमा यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को विपत्ति के समय में आर्थिक सहायता मिले। यह राशि हमारे अन्नदाता के लिए एक सहारा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को चेक वितरित किए और कल्याणकारी योजनाओं और समय पर वित्तीय सहायता के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से उत्पन्न अनिश्चितताओं से बचाया जाए और कल्याणकारी पहल पारदर्शी तरीके से लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।

लखनऊ दर्शन बस सेवा से विधानसभा की सैर पर्यटकों के लिये फिर से शुरू

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होते ही लखनऊ दर्शन बस सेवा से विधानसभा की सैर एक बार फिर पर्यटकों के लिये शुरू कर दी गयी है। बजट सत्र के दौरान सुरक्षा कारणों से विधानसभा भ्रमण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सत्र समाप्त होने के साथ ही विधानसभा को दोबारा टूर में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भव्य स्थापत्य, विशाल गुंबद और ऐतिहासिक महत्व से परिपूर्ण विधानसभा भवन राजधानी की पहचान है और इसके शामिल होने से लखनऊ दर्शन और आकर्षक हो गया है। टूर का एक प्रमुख आकर्षण जनरल पोस्ट ऑफिस लखनऊ (पूर्व रिंग थियेटर) भी है। नौ अगस्त 1925 के काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने यहां विशेष अदालत बनाकर करीब 10 महीने तक मुकदमा चलाया था। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि शचीन्द्रनाथ सान्याल को कालापानी और मन्मथनाथ गुप्त सहित अन्य को कठोर कारावास मिला। आज

यहां स्थित संग्रहालय में उस दौर की यादें संरक्षित हैं, जिन्हें पर्यटक देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) की लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा प्रतिदिन सुबह और शाम दो पालियों में 1090 चौराहे से संचालित होती है। यह बस राजधानी के प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थलों का भ्रमण कराती है। टिकट आधिकारिक वेबसाइट या प्रस्थान स्थल से प्राप्त की जा सकती है। किराया वयस्कों के लिए 500 रुपये और बच्चों के लिए 400 रुपये निर्धारित है। बस में प्रशिक्षित टूर गाइड उपलब्ध रहते हैं। इलेक्ट्रिक बस होने के कारण यह यात्रा पर्यावरण के अनुकूल और आरामदायक भी है।

संक्षिप्त

यूपी बोर्ड परीक्षा में लापरवाही पर डीएम सख्त, 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों का वेतन रोका

संवाददाता

लखनऊ। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा–2026 के दौरान ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। निरीक्षण में 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने परीक्षा केंद्रों से अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सभी संबंधित अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया है। स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा–2026 को सकुशल, निर्विघ्न और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद के 121 परीक्षा केंद्रों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था। इसके लिए 6 फरवरी 2026 को जारी अलग–अलग आदेशों के माध्यम से अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई थी। इनका दायित्व परीक्षा केंद्रों पर कानून–व्यवस्था बनाए रखना, नकल रोकना और परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा 18 फरवरी 2026 को भेजी गई आख्या में यह जानकारी दी गई कि प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान 19 परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु उपस्थित नहीं हुए। यह तथ्य सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि संबंधित अधिकारियों ने न तो समय पर उपस्थिति दर्ज कराई और न ही अनुपस्थिति की पूर्व सूचना दी। इसे जिलाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना माना गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ को पत्र भेजकर संबंधित 19 अधिकारियों, कार्मिकों का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने इसे उदाहरणात्मक कार्रवाई बताया है, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी परीक्षा ड्यूटी को हल्के में न ले।

एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर मायावती का बड़ा बयान, कहा, देश की छवि को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं

संवाददाता

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध–प्रदर्शन पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस घटना को अति–अशोभनीय व निन्दनीय करार देते हुए कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में इस प्रकार का आचरण देश की गरिमा और छवि को प्रभावित करता है। अपने आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित इस समिट में देश और विदेश के कई प्रमुख लोग आमंत्रित थे और यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे में कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर विरोध प्रकट करना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह प्रदर्शन किया, उनमें अधिकतर कांग्रेसी

युवा बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर का न होता तो बात अलग हो सकती थी, लेकिन वैश्विक मंच पर इस तरह की घटनाएं देश की इमेज को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मायावती ने सभी राजनीतिक दलों और युवाओं से अपील की कि विरोध दर्ज कराना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसका तरीका मर्यादित और जिम्मेदार होना चाहिए।

बीमा संस्थान ने डिजिटल सुरक्षा पर सेमिनार किया

ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए किया जागरूक

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ बीमा संस्थान और हेल्प पेज इंडिया ने हजरतगंज स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कार्यालय में एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का विषय 'डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल सुरक्षा' रहा। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम में

बीमा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। सेमिनार का मुख्य लक्ष्य डिजिटल युग में लोगों को सुरक्षित, सतर्क और जागरूक बनाना रहा। सेमिनार की अध्यक्षता सेवानिवृत्त मंडल प्रबंधक एस.जी.पी. त्रिपाठी ने की। उन्होंने बीमा क्षेत्र में हो रही डिजिटल पहलों की जानकारी दी और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने पर जोर दिया। त्रिपाठी ने कहा कि डिजिटल सुविधाएं जितनी आवश्यक हैं, उतना ही जरूरी उनका सुरक्षित उपयोग समझना है।कार्यक्रम की मुख्य वक्ता हेल्पएज इंडिया की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रश्मि मिश्रा रहीं। उन्होंने बताया कि यह सेमिनार लखनऊ बीमा संस्थान और हेल्पएज इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 60 से 70 वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। मिश्रा ने प्रतिभागियों को ऑनलाइन ठगी से बचाव, मजबूत पासवर्ड बनाने की तकनीक, मोबाइल और अन्य उपकरणों की सुरक्षा, अनजान कॉल से सतर्क रहने तथा डिजिटल जोखिमों से बचने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल अरेस्ट, बैंक फ्रॉड और साइबर अपराध के नए–नए तरीके सामने आ रहे हैं, इसलिए जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। लखनऊ बीमा संस्थान के अवैतनिक सचिव यू.पी. सिंह ने बताया कि संस्थान साधारण बीमा और एलआईसी से संबंधित शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। संस्थान समय–समय पर बीमा जागरूकता कार्यक्रम और जनहित से जुड़े सेमिनार आयोजित करता रहता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्षरता आज की जरूरत है और हेल्पएज इंडिया के सहयोग से इस विषय पर प्रभावी चर्चा की गई। सेमिनार में अमित कपूर (सेवानिवृत्त क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी), देवेंद्र मिश्रा, प्रमोद श्रीवास्तव, मोहित, आयुष मिश्रा और शिवांशु शुक्ला सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

'दुर्लभ न्यूरो-इंटरवेंशनल प्रक्रिया से ढाई वर्ष की बच्ची को मिल नया जीवन'

संवाददाता

लखनऊ। अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ न्यूरो–इंटरवेंशनल प्रक्रिया इंट्राक्रेनियल कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस कर ढाई साल की बच्ची की जान बचाई। यह उन्नत मस्तिष्क प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में पहली बार की गई। इस प्रक्रिया को इंटरवेंशनल न्यूरो–रेडियोलॉजिस्ट डॉ. देवांश मिश्रा ने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टीम के डॉ. अर्पित टौंक और डॉ. अमोल श्रीवास्तव के साथ मिलकर पूरी की। बच्ची को अचानक बेहोशी, हाथ–पैरों में लकवा जैसे लक्षण और बार–बार बेहोश होने की स्थिति में गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। आपातकालीन जांच में एमआरआई, सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी से मस्तिष्क की गहरी शिरा में खून का थक्का पाया गया। इस स्थिति को सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, जो समय पर उपचार न मिलने पर गंभीर मस्तिष्क को गहरे नुकसान या मृत्यु का कारण बन सकती है। बाल रोग विभाग की टीम ने प्रारंभ में स्टैंडर्ड इलाज शुरू किया। जिसमें डॉ. सिद्धार्थ कुँवर, डॉ. सिद्धार्थ

और डॉ. निशांत गोपाल शामिल रहे। लेकिन स्थिति की गंभीरता और सीमित सुधार को देखते हुए चिकित्सकों ने इंट्राक्रेनियल कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस करने का फैसला लिया। इतनी कम उम्र के मरीज में यह प्रक्रिया बेहद दुर्लभ मानी जाती है।प्रक्रिया के दौरान पैर में एक छोटा छेद कर सूक्ष्म कैथेटर डाला गया और उसे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क की प्रभावित गहरी शिरा तक सावधानीपूर्वक पहुंचाया गया। इसके बाद थक्का घोलने वाली दवा सीधे उसी स्थान पर दी गई। चार दिनों तक लगातार निगरानी के साथ सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी की गई, जिसके बाद थक्का पूरी तरह घुल गया।इसके बाद बच्ची को इंटेंसिव केयर में रखा गया, धीरे–धीरे वेंटिलेटर से हटाया गया और विशेष चिकित्सा देखरेख जारी रही। लगभग तीन सप्ताह के उपचार के बाद उसे स्थिर अवस्था में छुट्टी दे दी गई। वर्तमान में वह चलने, बोलने और सामान्य दैनिक गतिविधियां करने में सक्षम है। डॉ. देवांश मिश्रा ने कहा, "मस्तिष्क की गहरी शिराओं में खून का थक्का बनना बच्चों में अत्यंत गंभीर और जानलेवा स्थिति होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा लिटरेचर में भी बहुत कम दर्ज है और उत्तर प्रदेश में यह पहला मामला है। उन्होंने आगे बताया, "बच्ची एपीएलएस सिंड्रोम से ग्रसित थी, जो एक आनुवंशिक स्थिति है और इसमें खून के थक्के बनने की प्रवृत्ति अधिक होती है। संक्रमण और डिहाइड्रेशन के कारण स्थिति और बिगड़ गई। समय पर हस्तक्षेप न किया जाता तो उसे बचाना संभव नहीं था। देश में दर्ज पीडियाट्रिक स्ट्रोक का यह पहला मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। इस जटिल और चुनौतीपूर्ण केस को 12 से 15 मार्च तक कोच्चि में आयोजित इंडियन नेशनल स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। इस सम्मेलन में देशभर से आए वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट और स्ट्रोक विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे और स्ट्रोक उपचार की नई पद्धतियों, जटिल मामलों के प्रबंधन तथा ताजा शोध पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के एमडी और सीईओ डॉ. मयंक सोमानी ने इसे उन्नत न्यूरो–इंटरवेंशनल देखभाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य है कि सबसे जटिल उपचार भी सुरक्षित, सुलभ और असरदार रूप से उपलब्ध हों। इस दुर्लभ प्रक्रिया की सफलता दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में ही विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।"

डंडा और झंडा लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की ओर कूच का समाचार मिलते ही एनएसयूआई कार्यकर्ता एक्टिव हो गए। हाथों में डंडा और तिरंगा झंडा लेकर कार्यालय के बाहर आए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। वहीं "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर है" जैसे नारे लगाए। इससे माहौल गरमा गया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से जुलूस के रूप में आगे बढ़े। कार्यालय से कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही उन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान मौके पर काफी देर तक नारेबाजी होती रही।

'जहां दवाएं रुक जाएं, वहां सर्जरी उम्मीद बनती है'

लखनऊ में उन्नत मिर्गी सर्जरी पर जागरूकता कार्यक्रम'

संवाददाता

लखनऊ। मिर्गी को लेकर समाज में आज भी कई तरह के भ्रम और डर मौजूद हैं, जबकि यह मस्तिष्क से जुड़ा सामान्य रोग है जिसका इलाज संभव है। इसी उद्देश्य से लखनऊ में आयोजित जन–जागरूकता कार्यक्रम में अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कोच्चि के एडवांस्ड एपिलेप्सी सेंटर के निदेशक डॉ. सिबी गोपीनाथ और मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डॉ. अनूप कुमार ठक्कर ने मिर्गी सर्जरी के महत्व पर विस्तार से चर्चा की।भारत में लगभग 1.50 करोड़ लोग मिर्गी से प्रभावित हैं। अच्छी बात यह है कि सही दवाओं से 70 प्रतिशत से अधिक मरीजों में दौरे पूरी तरह नियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन लगभग 30 प्रतिशत मरीज ऐसे होते हैं जिन के लिए दवाएं असर नहीं करतीं। ऐसे मामलों में सर्जरी सुरक्षित और प्रभावी विकल्प हो सकती है। डॉ. सिबी गोपीनाथ ने कहा, "मिर्गी सर्जरी डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। सही जांच के बाद चुने गए मरीजों में सर्जरी से दौरा–मुक्त जीवन संभव है। कई मरीजों में ऑपरेशन के बाद दवाएं भी धीरे–धीरे बंद की जा सकती हैं।"डॉ अनूप कुमार ठक्कर ने बताया, "जहां दवाएं काम न करें, वहां मिर्गी सर्जरी आशा देती है। यह खर्च नहीं, जीवन में निवेश है। हम पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि दौरे मस्तिष्क के किस हिस्से से शुरू हो रहे हैं, फिर उसी के अनुसार इलाज की योजना बनाई जाती है।"विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर चार में से तीन मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। अंधविश्वास, सामाजिक कलंक और जानकारी की कमी इसके बड़े कारण हैं। अनुमान है कि देश में लगभग 50 लाख मरीज सर्जरी के योग्य हो सकते हैं लेकिन हर साल केवल करीब 1,000 सर्जरी ही हो पाती हैं। आधुनिक जांच तकनीकों से यह पता लगाया जा सकता है कि दौरे मस्तिष्क के किस हिस्से से शुरू हो रहे हैं लेकिन ऐसी सुविधाएँ देश के गिने–चुने उन्नत केंद्रों तक सीमित हैं। दूरी, खर्च और स्थानीय संसाधनों की कमी के कारण अधिकांश मरीज वहाँ पहुँच नहीं पाते। अनुमान है कि देश में लगभग 50 लाख लोग सर्जरी के योग्य हो सकते हैं इसलिए जागरूकता बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि हर मिर्गी लाइलाज नहीं होती। सही समय पर सही केंद्र में जांच और परामर्श से हजारों मरीज सामान्य और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। लखनऊ में विशेषज्ञों की यह पहल उत्तर भारत में उन्नत मिर्गी सर्जरी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

नाइस फिल्म प्रोडक्शन ने निभाए अपने वादे

इंडियास आइकोनिक टैलेंट शो सीजन 1 के विनर और रनर अप को मिल रहा है बड़ा मंच'

संवाददाता

लखनऊ। नाइस फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले आयोजित इंडियास आइकोनिक टैलेंट शो सीजन–01 के ग्रैंड फिनाले (16 अगस्त 2025) में किया गया वादा अब हकीकत बन चुका है। शो के दौरान घोषणा की गई थी कि जो भी प्रतिभागी इस मंच से विजेता या रनर–अप बनकर निकलेंगे, उन्हें म्यूजिक वीडियो एल्बम के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा कृ और नाइस फिल्म प्रोडक्शन ने इस वादे को पूरा कर दिखाया है।सीजन–01 के प्रतिभागियों को मौका देते हुए अब तक 4 से अधिक म्यूजिक एल्बम लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग और किड्स कैटेगरी के प्रतिभाशाली बच्चों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। लॉन्च हुए प्रमुख म्यूजिक एल्बम "हवा हो गए" अमरेंद्र सिंह व शीतल कुशवाहा ने लीड रोल निभाया। "तेरा लाल लहंगा" दृ किड्स कैटेगरी के फर्स्ट विनर एलिस रिहान सहित डांसिंग–मॉडलिंग के प्रतिभागी रुद्र प्रताप सिंह, इनाया दहल, आर्यन खान, अर्णव खान और अंशुमान गुर्जर ने लीड रोल किया।"कभी तुम्हें" दृ सिंगिंग कैटेगरी के विजेता ज्ञानेंद्र तिवारी और लीना चौहान की आवाज में रिलीज।"आसमान की तरफ" आर्यन खान, अर्णव खान और इनाया दहल की म्यूजिक स्टोरी वीडियो, जिसे दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया और रिलीज के कुछ ही दिनों में 5 लाख से अधिक व्यूज प्राप्त हुए। इन सभी गीतों को बड़े प्लेटफार्म पर लॉन्च किया गया है स्पॉटिफाई जिओ हंगामा एप्पल म्यूजिक मानी जानी म्यूजिक कंपनी में लॉन्च किया गया दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और व्यूज लगातार लाखों में पहुंच रहे हैं। आगे की बड़ी योजना नाइस फिल्म प्रोडक्शन ने घोषणा की है कि आने वाले समय में उनके बैनर तले 100 से अधिक नए म्यूजिक एल्बम बनाए जाएंगे, जिनमें सिंगर, एक्टर, मॉडल और किड्स कैटेगरी के नए–नए प्रतिभागियों को मौका दिया जाएगा।

नगर निगम के सदन में पार्षदों में तीखी बहस, भाजपा पार्षद ने वाकआउट किया

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम का सदन शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी बहस और तनातनी हो गई। भाजपा पार्षद के बोलने पर कांग्रेस वाले ने कहा कि आप बार–बार न बोलिए। इसके बाद दोनों पक्षों में स्थिति यहां तक पहुंची कि अन्य पार्षदों को बीच में आना पड़ा। दरअसल, कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान सदन का एजेंडा न मिलने का विरोध कर रहे थे। इस बीच भाजपा पार्षद अन्नू मिश्रा कुछ बोलने लगे तो उन्होंने मना किया कि वह बार–बार न बोलें। इसी पर दोनों में तकरार हो गई। इसी दौरान कांग्रेस पार्षद ममता रावत अन्नू के करीब पहुंच गईं और उन्हें शांत कराने लगीं। मामला शांत हुआ तब सदन शुरू हुआ। इस बीच भाजपा पार्षद नागेंद्र सिंह ने सदन का बहिष्कार कर वाकआउट कर दिया। मेयर सुषमा खर्कवाल ने यह विशेष सदन बुलाया था। इसमें पहले से कोई विषय या एजेंडा न होने पर पक्ष–विपक्ष के सभी पार्षद विरोध करने लगे।

बारात के दौरान हर्ष फायरिंग में एलडीए के ड्राइवर की मौत

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में हर्ष फायरिंग में 49 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। शुक्रवार रात अपने दोस्त के बेटी की शादी में शामिल होने गए थे। तभी बारात के दौरान किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी गोली उनके पैर में जाकर लगी। आनन–फानन में घायल हालात में अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अलीगंज निवासी सुनील यादव (49) के रूप में हुई। वह एलडीए में कॉन्ट्रैक्ट में ड्राइवरी करते थे। शुक्रवार को विनयखंड गोमतीनगर में दोस्त राम किशोर दुबे के बेटे अभिषेक दुबे की विराट खंड स्थित सामुदायिक केंद्र में शादी थी। वहां पर बारात के दौरान हर्ष फायरिंग की गई।

एक बड़े तकनीकी विकास की तरफ अग्रसर हो चुका है बिहार

एआई के क्षेत्र में बिहार के नवाचार देखकर दुनिया दंग
केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी की सराहना

बीएनई

नई दिल्ली। देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हुए बिहार ने टेक्नोलाजी की दुनिया में भी बेहद मजबूती के साथ अपना कदम रखा है। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बिहार पैवेलियन न सिर्फ देश के विकसित राज्यों के, बल्कि दुनिया भर से आए टेक विशेषज्ञों के बीच आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ एआई के इस्तेमाल की जो झलक पेश की गई है, उसे देखकर दुनिया दंग है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 के समापन दिवस पर शनिवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार पैवेलियन का दौरा किया।

अपने भ्रमण के दौरान मंत्री ने राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा प्रदर्शित एआई–सक्षम चुनावी नवाचारों की सराहना की। इन नवाचारों में सुरक्षित ई–वोटिंग समाधान तथा नागरिक–केंद्रित मोबाइल अनुप्रयोग विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शी और सुरक्षित चुनावी प्रणाली लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार द्वारा प्रस्तुत डिजिटल पहलों से यह स्पष्ट है कि राज्य सुशासन और तकनीकी नवाचार के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी एवं सहभागी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का दायरा अब केवल तकनीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारत के बुनियादी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने अमेरिका के कैलिफोर्निया से आए महेश ने विभिन्न क्षेत्रों में एआई के भविष्य और इसके सामाजिक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की। महेश बिहार के नवगछिया के रहने वाले हैं और उनका जन्म से लेकर उनकी शिक्षा–दीक्षा बिहार में ही हुई है। उनकी कंपनी टाइगर एनालिटिक्स के साथ बिहार सरकार ने विगत मंगलवार को ही एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं। उन्होंने कहा कि एआई के जरिये बिहार मुख्यतरू कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चुका है।

बिहार के किसान करेंगे अब "स्मार्ट खेती"

महेश बताते हैं कि कृषि के लिए बिहार अब "स्मार्ट खेती" की तरफ अग्रसर है। एआई किसानों के लिए एक डिजिटल सलाहकार के रूप में उभर रहा है। सेंसर और सैटेलाइट डेटा के जरिए किसान मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों और फसल के स्वास्थ्य की रीयल–टाइम निगरानी कर सकेंगे। किसान ई–मित्र जैसे एआई चौटबॉट और मोबाइल ऐप फोटो के जरिए फसल की बीमारियों को पहचान कर उनका समाधान बता रहा है। इतना ही नहीं, एआई आधारित मॉडल मौसम की सटीक भविष्यवाणी करते हैं और किसानों को बाजार भाव का पूर्वानुमान बताकर बेहतर कमाई में मदद करेंगे।

एआई से होगी बीमारियों की पहचान और इलाज

इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर घर तक इलाज के लिए एआई अस्पताल की दूरी और सुविधाओं की कमी को खत्म कर रहा है। अब बीमारियों का त्वरित इलाज के लिए उपकरण जैसे एक्सरे और सीटी स्कैन का कुछ क्षणों में ही विश्लेषण कर टीबी और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह, एआई संचालित स्टेथोस्कोप और थर्मल इमेजिंग से ग्रामीण क्षेत्रों में हृदय रोग और ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती जांच संभव हो रही है।

एआई से बढ़ेगी छात्रों में सीखने की क्षमता

एक अन्य प्रतिभागी दीपक बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एआई हर छात्र की सीखने की क्षमता के हिसाब से बदलाव ला रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पोलिटेक्निक संस्थानों के 10 से 20 हजार छात्रों को एआई के क्षेत्र में दक्ष बनाया जाएगा। उन्हें इंटर्नशिप देकर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा।

बहुभाषी रोबोट देगा किसी भी भाषा में आपके सवालों का जवाब

बिहार पैवेलियन में बहुभाषी रोबोट सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस रोबोट के जरीय रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों या होटलों में रेसेप्सनिस्ट का काम लिया जा सकता है। यह रोबोट दुनिया की किसी भी भाषा में बात कर सकता है और उससे बात करने वालों के सभी सवालों का उनकी ही भाषा में जवाब दे सकता है। बिहार पैवेलियन में एआई के ऐसे संसाधन भी मौजूद हैं जो बिना बिना मानव बल के कचरा साफ़ करने, बड़े–बड़े नालों की सफाई में सक्षम है।

लोकतंत्र का आधुनिकीकरण

बिहार पैवेलियन में मौजूद बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार यानी चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने में एआई के इस्तेमाल की जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव में मतगणना को लेकर कई तरह के आरोप–प्रत्यारोप से अब जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है। उन्होंने मतगणना में एआई के इस्तेमाल की जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना को निष्पक्ष बनाने के लिए बिहार एआई के इस्तेमाल के लिए तैयार है। इसमें एआई के जरिये मतगणना स्थल के अंदर की सभी जानकारी मतगणना स्थल के बाहर खड़े लोग देख सकते हैं। इतना ही नहीं, मतदान केंद्रों पर विसंगतियों और सुरक्षा की निगरानी के लिए भी अब एआई आधारित सर्विलांस का उपयोग किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने बिहार कैंसर कॉन्क्लेव-2026 का दीप प्रज्ज्वलित कर किया उद्घाटन

बीएनई

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बुद्ध मार्ग स्थित ताज होटल में बिहार कैंसर कॉन्क्लेव–2026 का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया। आयोजकों ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिह्न एवं पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन 21 एवं 22 फरवरी को किया गया है, जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित चिकित्सक और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। बिहार कैंसर कॉन्क्लेव–2026 में कैंसर के निदान, उपचार और रोगियों के नवीनतम सेवाओं के संबंध में मंथन किया जायेगा। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार में कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जायेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एस०एम०, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के० शर्मा, डॉ० ए०ए० हई, डॉ० अभिषेक आनंद सहित अन्य चिकित्सकगण एवं वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीय निर्यातकों को राहत! जानें किन उत्पादों पर होगा असर

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए टैरिफ के स्थान पर वे अगले 150 दिनों के लिए दुनिया के सभी देशों पर 10 फीसदी का वैश्विक शुल्क लगाने का एलान किया है। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए व्यापक टैरिफ को रद्द करने के फैसले का भारतीय निर्यातकों ने स्वागत किया है। निर्यात संगठनों का कहना है कि इस निर्णय से उन भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो देश–विशेष शुल्क से प्रभावित थीं। अब भारत पर 18 की जगह 10 फीसदी टैरिफ? 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत जारी किया जाएगा और ये शुल्क इसी कानून के तहत लागू मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त होंगे। दूसरे शब्दों में, जिन देशों पर आपातकालीन शक्तियों के तहत ट्रंप ने 10 फीसदी से अधिक टैरिफ लगाया था वह खत्म हो जाएगा और सिर्फ 10 फीसदी टैरिफ रह जाएगा। इसका भारत पर भी सीधा असर होगा जिसपर ट्रंप ने 18 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। यह अब 10 फीसदी रह जाएगा। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा कि इस फैसले से भारत–अमेरिका व्यापार में स्थिरता आएगी और भविष्य को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अमान्य किए गए टैरिफ के तहत जिन आयातकों ने शुल्क चुकाया है, वे अब धन वापसी का दावा कर सकते हैं, जिससे कारोबार को तुरंत राहत मिल सकती है। इन उत्पादों को मिल सकती है राहत वैश्विक व्यापार शोध पहल के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि अगर अमेरिका भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ भी हटाता

है, तो भारत के लगभग 55 प्रतिशत निर्यात पर केवल सामान्य सीमा शुल्क ही लागू रहेगा। हालांकि इस्पात, एल्युमीनियम और कुछ वाहन पुर्जों पर धारा 232 के तहत लगाए गए 50 और 25 प्रतिशत शुल्क अभी भी लागू रहेंगे। वहीं मोबाइल फोन, पेट्रोलियम उत्पाद और दवाइयों जैसे उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ नहीं लगेगा। फैसले से अमेरिका में बढ़ सकती है अराजकता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पर अकेले चलने की कीमत चुकानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले से चुनाव वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक अराजकता और अनिश्चितता और बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी यह पता नहीं है कि वसूला गया टैरिफ वापस होगा या नहीं। वहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है कि देशों पर लगे टैरिफ की भविष्य में क्या स्थिति होगी। हर 10 में से 6 अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप ने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर सारी हद पार कर दी है। वहीं, ट्रंप ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि फैसला शर्मनाक है। उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ट्रंप ने फैसले की जानकारी मिलते ही कहा, मुझे इन अदालतों के बारे में कुछ करना होगा। माना जा रहा है कि ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय रखेंगे। अमेरिका, यूरोप और एशिया के शेयर बाजारों में तेजी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ रद्द किए जाने के बाद शुक्रवार को अमेरिका, यूरोप और एशिया के शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। अमेरिका का एस एंड पी 500 सूचकांक 0.3 प्रतिशत चढ़ा। यूरोप में ऑटो शेयरों में उछाल आया, जबकि दक्षिण कोरिया से भारत तक बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।

गुयाना के उपराष्ट्रपति ने किया रामलला का दर्शन-पूजन

परिसर में बने अन्य मंदिरों में भी जाकर शीश झुकाया डॉ. भरत जगदेव ने

बीएनई

अयोध्या। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉ. भरत जगदेव शनिवार को रामनगरी पहुंचे। उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ रामलला का दर्शन–पूजन किया। उन्होंने परिसर में बने अन्य मंदिरों में भी जाकर शीश झुकाया। उपराष्ट्रपति लगभग एक घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। भव्य–नव्य अयोध्या देखकर वे प्रफुल्लित हो उठे। इसके पहले शनिवार सुबह वे प्रतिनिधिमंडल के साथ निजी विमान से वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे। शंखनाद व कलाकारों के भावपूर्ण नृत्य के बीच एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां खाद्य व रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, मिल्कीपुर के विधायक चंद्रभानु पासवान, कमिश्नर राजेश कुमार, डीआईजी सोमेन वर्मा, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने उनकी आगवानी की। एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए।

संक्षिप्त

छह साल के शीर्ष पर पहुंच सकता है सऊदी अरब से तेल का आयात

अमेरिकी दबाव से रूस से खरीद घटाने के असर

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत इस महीने सऊदी अरब से छह साल से अधिक समय में सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात करने जा रहा है। रूस से कच्चे तेल की खरीदारी कम करने के लिए अमेरिका के भारत पर लगातार दबाव बनाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। केप्लर के प्रमुख अनुसंधान विश्लेषक सुमित रितोलिया के अनुसार, सऊदी अरब से तेल की आपूर्ति बढ़कर 10 लाख से 11 लाख बैरल प्रतिदिन होने की संभावना है। यह नवंबर, 2019 के बाद से उच्च स्तर होगा। यह रूस के अनुरूप है, जिससे दोनों आपूर्तिकर्ताओं के बीच का अंतर काफी हद तक कम हो जाएगा। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद बढ़ाने के कारण यह अंतर काफी बढ़ गया था। भारत पर अमेरिकी दबाव इस महीने की शुरुआत में तब ज्यादा हो गया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत एक व्यापार समझौते के तहत रूसी तेल की खरीदारी बंद करने पर सहमत हो गया है। हालांकि, भारत ने इस दावे पर सार्वजनिक रूप से कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। अगर तेल का प्रवाह 12 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचता है।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम का निराशाजनक प्रदर्शन जारी, प्रो लीग मुकाबले में स्पेन से मिली हार

एजेंसी

होबार्ट। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का एफआईएच प्रो लीग में निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। टीम की नजरें वापसी पर लगी हुई थी, लेकिन उसे स्पेन से 0–2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत अब रविवार को प्रो लीग के होबार्ट चरण के अपने दूसरे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। भारतीय टीम की खराब फॉर्म जारी रही। स्पेन के लिए इग्नासियो अबाजो ने छठे मिनट और इग्नासियो कोबोस ने 36वें मिनट में गोल किए। मौकों को भुना नहीं सका भारत स्पेन की टीम ने मौकों का फायदा

उठाया, जबकि भारत लगातार आक्रमण के बावजूद अच्छे मौकों को भुना नहीं पाया। राउरकेला में घरेलू चरण में भारत को विरोधी टीमों से बुरी तरह हार मिली। बेल्जियम और अर्जेंटीना से दो–दो हार झेलने वाली भारतीय टीम विदेशी चरण के दौरान नए कप्तान हार्दिक सिंह के नेतृत्व में वापसी करने और नई शुरुआत करने की उम्मीद कर रही थी। भारतीय टीम ने कई अच्छे मौके बनाए और क्वार्टर के आखिर में लगभग बराबरी कर ही ली थी जब अभिषेक ने एक जोरदार शॉट लगाया लेकिन स्पेनिश गोलकीपर लुइस कैलजाडो ने इसका शानदार बचाव किया।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्तर प्रदेश का बेहतर प्रदर्शन

अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के बीच सोलर संयंत्र स्थापना में देश में दूसरा स्थान, घरेलू रूफटॉप सोलर में निरंतर वृद्धि
लखनऊ समेत 10 जनपदों में सर्वाधिक रूफटॉप सोलर स्थापित
सीएम योगी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के प्रति जनजागरूकता और स्वीकार्यता में तेजी

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अगस्त 2025 से जनवरी 2026 की अवधि में राज्य सोलर संयंत्र स्थापना के मामले में देशभर में दूसरे स्थान पर रहा। इस दौरान घरेलू रूफटॉप सोलर संयंत्रों की मासिक स्थापना में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश के 10 प्रमुख जनपद लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, बरेली, प्रयागराज, आगरा, झांसी, रायबरेली, शाहजहांपुर और सहारनपुर में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यह राज्य में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ती जनजागरूकता और स्वीकार्यता को दर्शाता है।

महाराष्ट्र से प्रतिस्पर्धा, गुजरात को पीछे छोड़ा

इस अवधि में उत्तर प्रदेश का सीधा मुकाबला महाराष्ट्र और गुजरात से रहा। सौर ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय से अग्रणी रहे गुजरात को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने शीर्ष दो राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत की है। यूपीनेडा के निदेशक इंद्रजीत सिंह का कहना है कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की सौर नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, जिलावार निगरानी और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण का परिणाम है। देश में कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश वर्तमान में तीसरे स्थान पर है, जबकि

पीएमएसजीवाई के तहत आवेदनों की संख्या में प्रदेश दूसरे स्थान पर है।

इंस्टॉलेशन में हर माह वृद्धि

अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के बीच हर माह घरेलू सोलर कनेक्शनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना, सब्सिडी का सीधे उपभोक्ताओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण और डिस्कॉम स्तर पर त्वरित स्वीकृति प्रणाली ने योजना को गति दी है। बढ़ते बिजली बिल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने भी लोगों को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रेरित किया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योजना का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य देश के एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर प्रत्येक परिवार को स्वच्छ एवं मुफ्त ऊर्जा का लाभ दिलाना है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस योजना की सफलता से उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने के साथ–साथ राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक विद्युत उत्पादन पर दबाव कम होगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे हरित ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी।

पहले स्थान की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वर्तमान गति बनी रही तो आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान भी हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में विगत सात माह से लगातार शीर्ष दो स्थान में बने रहना राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू सोलर अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के साथ–साथ प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा रही है।

'लड़ाई तब होती है जब दो लोग आपस में भिड़ते हैं', कंगना से झगड़े पर बोलीं तापसी, दोस्ती को लेकर कही ये बात

एजेंसी

तापसी पन्नू और कंगना रनौत बॉलीवुड की दो ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने आउटसाइडर होने के बावजूद अपनी दम पर अपनी पहचान बनाई है। दोनों ही अपनी दमदार एक्टिंग के लिए भी सुर्खियां बटोरती हैं। लेकिन दोनों के बीच कैट फाइट भी काफी पुरानी है और अक्सर चर्चा में भी रहती है। हालांकि, तापसी पन्नू का कहना है कि उनकी तरफ से कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं है। यहीं नहीं वो कंगना को अपना सीनियर बताते हुए उनसे दोस्ती करने को भी तैयार हैं। मैंने कभी लड़ाई की ही नहीं यूट्यूब पर शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान तापसी पन्नू ने कंगना के साथ अपने विवाद पर प्रतिक्रिया दी। कंगना की बहन द्वारा तापसी को कंगना की 'सस्ती कॉपी', 'बी ग्रेड एक्ट्रेस' और 'शी–मैन' कहने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। हालांकि, इस विवाद पर अब तापसी का कहना है कि उन्होंने कभी झगड़ा शुरू नहीं किया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने कभी लड़ाई की है या नहीं। लड़ाई तब होती है जब दो लोग आपस में भिड़ते हैं। मैं कभी नहीं भिड़ी। आप ही बताइए क्या मैंने कभी उनके खिलाफ एक भी बात कही है? आप कहीं भी ये दिखा दें जब मैंने उनके खिलाफ कुछ भी बोला हो। मुझे सस्ती कॉपी कहे जाने पर कोई दिक्कत नहीं कंगना की सस्ती कॉपी वाली टिप्पणी पर तापसी ने कहा कि उनकी बहन ने मुझे 'सस्ती नकल' कहा। उनका कहना था कि चूंकि मैं यहां उतनी कमाई नहीं करती, इसलिए मैं सस्ती हूं। अगर वह (कंगना रनौत) इतनी प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, तो मुझे उनकी नकल कहे जाने से कोई आपत्ति नहीं है।

भारत में सस्ते होंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वाहन, आखिर कैसे मजबूर हुआ अमेरिका?

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत के पैक्स सिलिका में शामिल होने से सबसे बड़ा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चीन के एकाधिकार और आपूर्ति शृंखला की बाधाओं के कारण चिप की कीमतों में जो कृत्रिम उछाल रहता था, वह अब खत्म होगा। खनिजों की सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी आपूर्ति होने से चिप निर्माण की लागत कम होगी। इसका सीधा लाभ स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर

इलेक्ट्रिक वाहनों तक को मिलेगा, जिससे उनकी कीमतें कम होने का रास्ता साफ होगा। अमेरिका ने पैक्स सिलिका गठबंधन की रूपरेखा तैयार करते समय भारत को इसमें शामिल नहीं किया था। विशेषज्ञों का मानना था कि भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता अभी शुरुआती स्तर पर है। हालांकि, बीते दो वर्षों में भारत ने जिस तेजी से 10 सेमीकंडक्टर संयंत्र (एफएबीएस) स्थापित करने की ओर कदम बढ़ाए और 2 नैनो मीटर चिप डिजाइनिंग में महारत हासिल की, उसने अमेरिका सहित अन्य देशों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा के बिना वैश्विक आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा अधूरी है। भारत का इस समूह में आना यह सुनिश्चित करता है कि देश को कच्चे माल के लिए चीन का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। आपूर्ति शृंखला को हथियार बनाना मंजूर नहीं रू वैष्णव केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दो–टूक कहा कि भारत और अमेरिका का इस घोषणापत्र पर साथ आना दुनिया को संदेश है कि हम आपूर्ति श्रृंखला को हथियार बनाने की कोशिशों को नकारते हैं। उन्होंने कहा, 20वीं सदी तेल और इस्पात की थी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743